Popular Front of India

+91 11 2 9949902
popularfrontmail@gmail.com
www.popularfrontindia.org
/PopularFrontofIndiaOfficial
@PFIOfficial
/Pfiofficial

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली

24 फरवरी 2020

पॉपुलर फ्रंट की नेशनल जनरल असेंबली संपन्न;
देश और संविधान की रक्षा के लिए बड़े आंदोलन की शुरूआत की नागरिकों से अपील

केरल के मलप्पुरम जिले में आयोजित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तीन दिवसीय नेशनल जनरल असेंबली संपन्न हुई, इसके साथ ही असेंबली ने सभी नागरिकों, वर्गों और सिविल सोसायटी समूहों से अपील की है कि वे हमारे देश और उसके संविधान को सांप्रदायिक फासीवादी खतरों से बचाने के लिए एक बड़े आंदोलन का निर्माण करें। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ दिन–प्रतिदिन बढ़ते शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में बड़े पैमाने पर लोगों की हिस्सेदारी को सराहने के साथ–साथ, पॉपुलर फ्रंट की एनजीए की बैठक ने याद दिलाते हुए कहा कि यह लड़ाई थोड़े समय की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके साथ हमारे संविधान में दिए गए समान अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत होनी चाहिए।

एनजीए की बैठक में मौजूदा परिस्थितियों को सामने रखते हुए कुछ अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए।

एक प्रस्ताव में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की नेशनल जनरल असेंबली ने केंद्र सरकार से सीएए, एनआरसी और एनपीआर को हर हाल में लागू करने के फैसले को छोड़ने की मांग की। सरकार को चाहिए कि वह इस कानून के खिलाफ सड़कों पर आए लाखों नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करे और मध्यस्थता का रास्ता अपनाने के बजाय, नागरिकता कानून को सिरे से खत्म करे, जिसके कारण नागरिकों की एक बड़ी संख्या पर नागरिकता के अधिकार से वंचित होकर बेवतन हो जाने का खतरा है।

एक अन्य प्रस्ताव में एनजीए ने सभी गैर–बीजेपी सरकारों से सीएए के विरोध को लेकर अपने स्टैंड की सच्चाई का सबूत पेश करते हुए यह प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया कि वे अपने राज्यों में मौजूदा रूप में सीएए/एनपीआर/एनआरसी को लागू नहीं करेंगी। साथ ही एनजीए ने इन राज्यों से एनपीआर पर रोक लगाते हुए एक सरकारी आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया। पॉपुलर फ्रंट की एनजीए ने बीजेपी की केंद्र एवं राज्य सरकारों से मांग की कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दमनकारी तरीके अपनाना बंद करें।

एक अन्य प्रस्ताव में एनजीए ने कानून के अनुसार काम करने वाले संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करने और दबाने के लिए उसे निशाना बनाने और उसकी छवि खराब करने की बीजेपी सरकार की कोशिश पर कड़ा विरोध जताया और सरकार और उसकी एजेंसियों से संगठन के खिलाफ दमनकारी तरीके अपनाना और झूठी बातें फैलाना बंद करने की मांग की।

एनजीए ने यूपी के एक पुलिसिया राज्य में बदलने पर सख्त गुस्सा जताते हुए राज्य में लोगों के नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सेक्युलर समूहों से अपनी आवाज़ उठाने की अपील की।

एक और प्रस्ताव में पॉपुलर फ्रंट की एनजीए ने मस्जिद के निर्माण के लिए सरकार द्वारा दी गई ज़मीन को स्वीकार करने के सुन्नी वक़्फ बोर्ड के फैसले की निंदा की और यह कहा कि उन्होंने समुदाय की भावनाओं के खिलाफ ऐसा करके मुस्लिम समुदाय को धोखा दिया है।

एनजीए ने केंद्र सरकार से यह भी मांग की कि वह देश और उसकी अर्थव्यवस्था को तबाही से निकालने के लिए आवश्यक कदम उठाए और यह कहा कि गरीबी को छुपाने के लिए बनाई जा रही दीवारों से गिरती अर्थव्यवस्था को नहीं छुपाया जा सकता।

बैठक में पारित एक और प्रस्ताव में नेशनल जनरल असेंबली ने केंद्र सरकार से कहा कि वह जम्मू व कश्मीर में लगाई गई पाबंदियों को हटाए और नज़रबंद किए गए नेताओं और अन्य राजनैतिक कैदियों को तत्काल रुप से रिहा करे।

असेंबली ने आम चुनावों से पहले फिलिस्तीन में यहूदी बस्तियों के विस्तार के इजरायली कदम की निंदा की।

एक अन्य प्रस्ताव में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की नेशनल जनरल असेंबली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, इससे पिछड़े वर्गों और दलितों को ऊपर उठाने की आरक्षण की असल सोच ही कमज़ोर हो जाएगी। बैठक ने याद दिलाते हुए कहा कि आरक्षण के प्रावधान को बचाना जो कि एक नागरिक अधिकार है, नागरिकता के लिए जारी प्रदर्शनों में यह भी शामिल होना चाहिए।

तीन दिवसीय असेंबली का समापन नवनिर्वाचित चेयरमैन ओ.एम.ए. सलाम के भाषण के साथ हुआ, जिन्होंने संगठन के बुनियादी मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और सभी साथियों से सहयोग की अपील की।

अनीस अहमद
महासचिव
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
नई दिल्ली